

>

Title : Need to provide special financial package to the State of Himachal Pradesh for enabling the State to discharge its fiscal liabilities.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.): मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 12वें वित्त आयोग की तुलना में नॉनमेंटिव एप्रोच पर आधारित 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार देश के अन्य सभी राज्यों के व्यय में 126 प्रतिशत की बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए केवल मात्र 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदान की जाने की सिफारिश की गई है। इसके कारण हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर असामान्य प्रभाव पड़ रहा है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमिटेड लाइबिलिटीज के बोझ की वजह से बहुत खराब स्थिति में आ गई है।

प्रदेश को इस स्थिति से उबारने के लिए मेरा आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश सरकार को (1) चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश को स्पेशल फायनेंशियल असिस्टेंस के रूप में ₹0 1,500 करोड़ दिए जाएँ, (2) वर्ष 2011-12 के लिए स्पेशल प्लान असिस्टेंस के रूप में दी जाने वाली धनराशि की सीमा ₹0 1,500 करोड़ तक बढ़ाई जाये एवं (3) 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश को दी जाने वाली स्टेट स्पेसीफिक ग्रांट को देते समय प्रदेश सरकार द्वारा फिस्कल डैफिसिट टारगेट पूरा करने की शर्त नहीं जोड़ी जाये।